



एनबीएफसी क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने वाले कारक

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-III
(भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

लेखक- जॉर्ज मैथ्यू (संपादक)

2 नवम्बर, 2018

“गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में तरलता की कमी ही सरकार और आरबीआई के बीच चल रहे संघर्ष की जड़ है। इस विवाद का मुख्य कारण क्या है? आरबीआई और सरकार के विचार किस मुद्दे पर अलग हैं? और आगे क्या होगा? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें ढूंढना चाहिए।”

भारत की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) क्षेत्र, जिसे शैडो बैंकिंग (shadow banking) प्रणाली भी कहा जाता है जो पारंपरिक वाणिज्यिक बैंकों के समान ही सेवाएं प्रदान करता है लेकिन सामान्य बैंकिंग नियमों के बाहर रहता है, वह इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (आईएलएंडएफएस) और तरलता की कमी के कारण बुरे दौर से गुजर रहा है। एनबीएफसी द्वारा सामना की जाने वाली तरलता की कमी ने सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच एक संघर्ष का निर्माण किया है, जिसमें जहाँ एक तरफ वित्त मंत्रालय आसान वित्त प्रवाह के लिए दबाव डालता आया है तो वहीं दूसरी तरफ आरबीआई जोर देकर कहता रहा है कि प्रणाली में पर्याप्त धन उपलब्ध है।

क्या है एनबीएफसी क्षेत्र में संकट?

कई निगमों, म्यूचुअल फंड और बीमा कंपनियों ने आईएल एंड एफएस समूह के कमर्शियल पेपर्स (CPs) और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) जैसे अल्पावधि उपकरणों में निवेश किया था जो अगस्त से ही भुगतान करने में नाकाम रहे हैं। जिसके बाद यह डर व्याप्त हो गया कि उनका धन आईएल एंड एफएस ऋण उपकरणों में फंस सकता है। 22 अक्टूबर, 2018 को 1.37 लाख करोड़ रुपये की घाटे के साथ तरलता की स्थिति गड़बड़ हो गई थी। इसके बाद यह भय बढ़ गया कि एनबीएफसी के लिए धन लागत और बढ़ेगी, जिसके परिणामस्वरूप उनके मार्जिन में तेज गिरावट आएगी।

क्या यह इस तथ्य का नतीजा है कि बैंक जो एनबीएफसी के सबसे बड़े उधारदाताओं में से थे, इन्होंने ही रोक लगाई है?

बैंकों ने एनबीएफसी को उधार देने की अपनी गति को धीमा कर दिया था, दरअसल बैंकों ने एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) के लिए एक प्रमुख संसाधन के द्वार को बंद कर दिया। हालांकि मूलभूत मुद्दा यह है कि आईएल एंड एफएस जैसे एनबीएफसी के संचालन में परिसंपत्ति-देयता मेल नहीं खाती है। इसका मतलब यह हुआ कि ये कंपनियां बाजार से धन उधार लेंगी अर्थात् 3 या 5 साल के लिए और लंबे कार्यकाल के लिए उधार देंगी अर्थात् 10 से 15 साल के लिए। ऐसे परिदृश्य में जहां ब्याज दरें बढ़ रही हैं, इससे एनबीएफसी को चोट पहुंचेगी, क्योंकि उनके मार्जिन दबाव में आ जायेंगे और धन को जुटाना मुश्किल हो जाएगा। डिफॉल्ट, संभावित निवेशकों को एचएफसी और एनबीएफसी के ऋण उपकरणों से दूर रखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात कि एनबीएफसी शेरों में हो रहे तेजी से नुकसान ने एक दुष्चक्र को जन्म दिया है, क्योंकि लाभ वाली स्थिति में घाटा अन्य शेरों की बिक्री को प्रोत्साहित करेगी, जिससे बाजारों को और नुकसान हुआ।

आरबीआई ने तरलता प्रदान करने के लिए क्या किया?

कुछ तिमाहियों से शिकायत आनी शुरू हो गयी थी कि आरबीआई ने तरलता देने में अपनी गति धीमी कर दी थी। 26 अक्टूबर को आरबीआई ने कहा कि वह नवंबर में त्यौहार के मौसम की मांग को पूरा करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद के माध्यम से प्रणाली में 40,000 करोड़ रुपये इंजेक्ट करेगा। यह अक्टूबर में खुले बाजार संचालन के माध्यम से दिए गये 36,000 करोड़ रुपये से अधिक है। एनबीएफसी क्षेत्र की निधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार और उद्योग ने एक स्पेशल विंडो के लिए दबाव डाला। आरबीआई ने केवल इस आधार पर इसे इनकार कर दिया कि एक बार एक स्पेशल विंडो या तरलता प्रदान करने के लिए की जाने वाली व्यवस्था स्थापित की जाती है, तो आरबीआई को वित्त की मांग करने वाली सभी कंपनियों को तरलता प्रदान करनी होगी। तर्क यह दिया गया कि इस क्षेत्र के लिए सामान्य चैनलों के माध्यम से पर्याप्त तरलता उपलब्ध है और आरबीआई एनबीएफसी की परिसंपत्ति गुणवत्ता का आकलन करने में सक्षम नहीं होगा कि कौन वित्त के लायक हैं और कौन नहीं हैं। इसने अपनी चिंताओं को भी व्यक्त किया कि इससे अन्य क्षेत्रों द्वारा भी इसी तरह की मांग की जा सकती है, जिससे नियामक के लिए नई समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

10 अक्टूबर को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कदम उठाए जाने से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एनबीएफसी को 45,000 करोड़ रुपये की अच्छी गुणवत्ता वाली संपत्ति खरीदने के प्रस्ताव के साथ जमानत देने की पेशकश की थी। एनबीआई ने पहले 15,000 करोड़ रुपये की संपत्ति खरीदने की योजना बनाई थी, फिर बाद में उसने 30,000 करोड़ रुपये तक अतिरिक्त संपत्ति खरीदने का फैसला किया है।

लेकिन क्या आरबीआई ने अतीत में इस क्षेत्र को विशेष तरलता का समर्थन नहीं दिया था?

2008-09 में भारतीय रिजर्व बैंक ने वैश्विक वित्तीय संकट के बाद बैंकों को एनबीएफसी, म्यूचुअल फंड और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को उधार देने के लिए एक विशेष रेपो विंडो की पेशकश की थी। जुलाई, 2013 में भी आरबीआई द्वारा बैंकों के लिए 25,000 करोड़ रुपये की तीन दिवसीय विशेष तरलता खिड़की खोली गयी थी।



एनबीएफसी उद्योग कितना बड़ा है?

देखा जाये तो एनबीएफसी धीरे-धीरे वाणिज्यिक बैंकिंग का स्थान लेने की ओर बढ़ रहा है। जब बैंड लोन के चलते बैंकों ने अपना उधार कारोबार को धीमा कर दिया, तो एनबीएफसी ही उच्च गति से बढ़ने लगा। मार्च, 2018 तक, आरबीआई के साथ पंजीकृत 11,402 एनबीएफसी थे, जिनमें से 156 एनबीएफसी (एनबीएफसी-डी) जमा स्वीकार करने वाले थे और 249 प्रणालीबद्ध रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा एनबीएफसी (एनबीएफसी-एनडी-एसआई) स्वीकार कर रहे थे। मार्च, 2018 तक एनबीएफसी क्षेत्र के कुल बैलेंस शीट का आकार 22.1 लाख करोड़ रुपये था। 2017-18 में एनबीएफसी के शेयर पूंजीगत विकास में गिरावट आई थी, जबकि उधार 19.1% की वृद्धि हुई थी।

भारत में एनबीएफसी में सिर्फ वित्त कम्पनियाँ ही नहीं, बल्कि निवेशकों, बीमा, चिट फंड, निधि, व्यापारी बैंकिंग, स्टॉक ब्रोकिंग, वैकल्पिक निवेश इत्यादि में शामिल कंपनियों का एक बड़ा समूह भी शामिल है। एनबीएफसी बैंकों के लिए वित्तीय मध्यस्था की अनुपूरक भूमिका निभाते हैं। एनबीएफसी, विशेष रूप से शहरी और ग्रामीण गरीबों को अपनी माइक्रो फाइनेंस संस्थानों (एनबीएफसी-एमएफआई) और परिसंपत्ति वित्त कंपनियों सहित सेवाएं प्रदान करते हुए देश के वित्तीय समावेश एजेंडे में पूरक भूमिका निभाता है। इसके अलावा, कुछ बड़े एनबीएफसी - इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियाँ - विशेष रूप से बुनियादी ढांचे क्षेत्र को उधार देने में लगी हुई हैं और कुछ फ़ैक्टरिंग व्यवसाय में हैं, जिससे विभिन्न क्षेत्रों के विकास और वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। संक्षेप में, एनबीएफसी वित्तीय क्षेत्र में विविधता का निर्माण करता है।

एनबीएफसी का फंड स्रोत क्या है?

एनबीएफसी, वित्तीय प्रणाली से वित्त का सबसे बड़ा शुद्ध उधारकर्ता था, जिसमें 717,000 करोड़ रुपये के सकल भुगतान (ऋण) और मार्च, 2018 में 419,000 करोड़ रुपये के सकल प्राप्तियाँ थीं। सकल देनदारियों का एक खंड इंगित करता है कि बैंकों से उच्चतम धन प्राप्त हुआ (44%), म्यूचुअल फंड (33%) और बीमा कंपनियों (19%) के बाद। एचएफसी 528,400 करोड़ रुपये के सकल भुगतान के साथ दूसरे सबसे बड़े उधारकर्ता थे और केवल 31,200 करोड़ रुपये के सकल प्राप्तियाँ थीं। मार्च 2018 तक, एचएफसी का उधार पैटर्न एनबीएफसी के समान था, सिवाय इसके कि वित्तीय संस्थानों ने भी एचएफसी को धन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एनबीएफसी की तरह, दीर्घकालिक ऋण, ऋण और कमर्शियल पेपर्स (CPs) शीर्ष तीन साधन थे जिसके माध्यम से एचएफसी ने वित्तीय बाजारों से धन जुटाने का कार्य किया था। अब, प्रणाली के साथ, जो तरलता की कमी का सामना कर रही है, म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियाँ और अन्य बड़े निवेशकों द्वारा एनबीएफसी में बड़े पैमाने पर निवेश करने की संभावना नहीं दिखती है। एनबीएफसी के लिए बैंकों का ऋण जोखिम मार्च, 2018 में छः हफ्तों की अवधि में 27% या 1 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 496,400 करोड़ रुपये हो गया था। हालांकि, बैंकों ने इस साल अप्रैल से अपने ऋण जोखिम घटाने शुरू कर दिए थे, और भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक एनबीएफसी के संपर्क में गिरावट 4.6% की आई है। मार्च, 2017 में बैंकों का बकाया क्रेडिट 391,000 करोड़ रुपये था। बैंकों द्वारा एनबीएफसी के साथ संपर्क में अचानक वृद्धि ने ही आरबीआई को बैंकों को यह निर्देश देने के लिए मजबूर किया वे अपने ऋण जोखिम को कम करें।

एनबीएफसी के पास बचे विकल्प?

तरलता में आई कमी यह दर्शाता है कि एनबीएफसी के लिए वित्त प्रवाह धीमी पड़ जाएगी। बॉन्ड मार्केट में हाल ही में प्रतिकूल भावना का मतलब उधार लेने की लागत भी हो सकती है। विश्लेषकों का कहना है कि इनके द्वारा कम वृद्धि / मार्जिन देखने की संभावना बढ़ गयी है। दूसरी तरफ, ऐसी भी संभावना है कि आरबीआई एचएफसी और एनबीएफसी के लिए दिशानिर्देशों को और अधिक कठोर बनाएगा, जो उन्हें विनियमन के मामले में लगभग वाणिज्यिक बैंकों के बराबर ला खड़ा करता है। वर्ष 2008 के वित्तीय संकट के बाद, आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए कई कठोर मानदंड निर्धारित किए हैं। मार्च, 2017 के अंत तक न्यूनतम चरण-1 पूंजी आवश्यकता चरणबद्ध तरीके से 7% से 10% तक बढ़ा दी गई थी। मार्च, 2018 के अंत तक बैंकों के साथ संपत्ति वर्गीकरण मानदंड 180 दिनों से 90 दिनों तक चरणबद्ध तरीके से संशोधित किए गए थे। हालांकि सरकार ने आईएल एंड एफएस के बकाया पैसे देने की घोषणा की है, जो सरकार के संकट की गंभीरता को रोकने के इरादे को दर्शाती है, आरबीआई से तरलता में आई कमी को बेअसर करने की उम्मीद है, लेकिन एक आसान धन अवधि (easy money period) का इतनी जल्दी वापस आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है।

GS World टीम...

इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (IL&FS)

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी विभिन्न बड़ी परियोजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभानेवाली कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (आईएल एंड एफएस) दिवालिया हो गयी है।
- यह अपने 91,000 हजार करोड़ से ज्यादा का कर्ज चुकाने में भी असमर्थ है।
- इसके कारण शेयर बाजार पर बुरा असर पड़ा है। साथ ही इससे कई बड़े बैंकों पर भी संकट मँडरा रहा है, भविष्य निधि व पेंशन निधि में जमा आम लोगों की मेहनत की कमाई डूब जाने के हालात पैदा हो गये हैं।
- विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में पैसा लगाने को लेकर चिंतित दिख रहे हैं। इस संकट को दूर करने के लिए मोदी सरकार ने आईएल एंड एफएस को अपने नियंत्रण में ले लिया है।



क्या है?

- इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज यानी 'आईएल एंड एफएस' सरकारी क्षेत्र की कंपनी है।
- इसकी कई सहायक कंपनियाँ हैं और इसे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (एनबीएफसी) का दर्जा भी मिला हुआ है।
- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी ने साल 1987 में इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढाँचे की परियोजनाओं को कर्ज देने के उद्देश्य के साथ आईएल एंड एफएस का निर्माण किया था।
- आईएल एंड एफएस एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जिसकी 40 सहायक कंपनियाँ हैं।
- इस कंपनी में दूसरी कंपनियाँ निवेश करती हैं और आम जनता इसके शेयर खरीदती है।
- इस कंपनी को कई रेटिंग एजेंसियों ने अति सुरक्षित रैंक दी हुई है।
- हाल ही में इस कंपनी ने 250 करोड़ रुपये के इंटरैस्ट पेमेंट का डिफॉल्ट कर दिया। यानी कंपनी अपनी कर्ज की किश्त नहीं चुका पाई।
- आईएल एंड एफएस कंपनी भारत सरकार का एक 'शैडो बैंक' है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे 'कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी' करार देता है।

क्या है संकट?

- इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (आईएलएंडएफएस) कंपनी समूह पर 91, 000 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है, जिसमें 57,000 करोड़ रुपये का अकेले बैंक ऋण है।
- पैसों की कमी की वजह से यह समूह अपने कर्जों की किश्त चुका पाने में असमर्थ है।

- इस वजह से न केवल कई बड़े बैंकों पर संकट मंडरा रहा है, बल्कि भविष्य निधि और पेंशन निधि में जमा आम लोगों की मेहनत की कमाई भी दाँव पर लग गयी है।

कैसे हुई संकट की शुरुआत?

- संकट की शुरुआत तब हुई, जब सितंबर में सिडबी (स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया) से लिए गये अल्पावधि ऋण को चुकाने में आईएल एंड एफएस असफल रही।
- डिफॉल्ट होने की वजह से आईएल एंड एफएस की रेटिंग लगातार गिरने लगी।

- कंपनी ने छोटी अवधि में लौटाने वाला बहुत ज्यादा कर्ज ले लिया और उसकी तुलना में उतनी आमदनी नहीं हो रही थी।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी) क्या हैं?

- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी उस संस्था को कहते हैं जो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत है और जिसका मुख्य काम उधार देना तथा विभिन्न प्रकार के शेयरों, प्रतिभूतियों, बीमा कारोबार तथा चिटफंड से संबंधित कार्यों में निवेश करना है।
- गैर बैंकिंग वित्त कंपनियाँ भारतीय वित्तीय प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। यह संस्थाओं का विजातीय समूह है (वाणिज्यिक सहकारी बैंकों को छोड़कर) जो विभिन्न तरीकों से वित्तीय मध्यस्थता का कार्य करता है जैसे:

- जमा स्वीकार करना।
- ऋण और अग्रिम देना।
- प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में निधियाँ जुटाना।
- अंतिम व्ययकर्ता को उधार देना।
- थोक और खुदरा व्यापारियों तथा लघु उद्योगों को अग्रिम ऋण देना।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारत में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे एवं लघु उद्योग संस्थानों को वित्तीय सेवाएं प्रदान की जाती है।
2. भारत में गैर-बैंकिंग कंपनियों के अंतर्गत केवल वित्त प्रदान करने वाली कंपनियों को शामिल किया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारत की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का विनियमन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों के समान किया जाता है।
2. शैडो बैंकिंग से तात्पर्य गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा वाणिज्यिक बैंकों जैसी सेवाएं प्रदान करना है, लेकिन यह बैंकिंग नियामक के कार्यवाहियों से बाहर रहती है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

- प्र. हाल ही में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की तरलता में आयी कमी, सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के मध्य विवाद का कारण माना जा रहा है, को स्पष्ट करते हुए समाधान के उचित उपाय बताएं। (250 शब्द)

नोट : 01 नवंबर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(a) और 2(d) होगा।

